प्रदेश का सबसे बड़ा बजट आज

7.5 लाख करोड़ से ज्यादा का होने का अनुमान, वित्त मंत्री ने दिया अंतिम रूप

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में सोमवार को पेश किए जाने वाले प्रदेश के बजट पर रविवार को हस्ताक्षर कर इसे अंतिम रूप दिया। इसका आकार 7.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), सौर ऊर्जा, धार्मिक पर्यटन, कृषि, उद्योग व एमएसएमई पर फोकस रहने की संभावना है। बजट में प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाने की झलक भी मिलेगी।

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सोलर पॉलिसी के तहत सोलर सिटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। युवाओं के लिए लैपटॉप और टैबलेट के लिए भी विशेष वित्तीय प्रावधान हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए पैकेज व ओडीओपी पर भी फोकस रहेगा। केंद्र सरकार की योजनाओं में राज्यांश की व्यवस्था पर भी केंद्रित होगा।

बजट में एआई के लिए भी शुरुआती 50 करोड़ रुपये का प्रावधान हो सकता है। ज्यूरिख (स्विटजरलैंड) की जिस नामचीन ईटीएच यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने पढ़ाई की थी, उसके साथ नोएडा की गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी में एक एआई सेंटर खोला जाना प्रस्तावित है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट और सैमसंग भी मदद करेगा। शासन में इन मामलों को डील करने के लिए एआई विभाग भी बनाने की योजना है। इस पर भी निर्णय संभव है। सोमवार को पहले कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बजट के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।

मुख्य थीम होगी समग्र विकास

- एआई, सोलर, धार्मिक पर्यटन, कृषि, उद्योग व एमएसएमई पर रहेगा फोकस
- प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाएगा

सर्व समावेशी होगा योगी-2 सरकार का तीसरा बजट

बजट को अंतिम रुप देने के बाद हस्ताक्षर करते वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। सूचना विभाग

वित्त मंत्री खन्ना ने कहा कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा सर्व समावेशी व सर्व स्पर्शी बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के समग्र विकास के साथ ही आधारभूत ढांचे के पुनर्निर्माण और गरीबों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं व किसानों को सम्मानजनक जीवन जीने के साथ उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने को समर्पित है। मुख्यमंत्री के वित्तीय अनुशासन और मार्गदर्शन में प्रदेश की अर्थव्यवस्था निरंतर सुदृढ़ हो रही है।

- वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट सभी आधुनिक मापदंडों पर चलने का एक दस्तावेज है। इसमें ऐसी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिससे कि सभी नागरिक प्रदेश के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे सकें। कंधे से कंधा मिलाकर बिना किसी भेदभाव के आपसी भाईचारे के साथ प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे।

बजट वित्त वर्ष 2023-2024

6,90,242 करोड़ रुपये का

32,721 करोड़ की थीं नई योजनाएं

केंद्रीय बजट का सर्वाधिक लाभ भी यूपी को

- वित्त मंत्री के अनुसार एक फरवरी को प्रस्तुत हुए केंद्र सरकार के अंतरिम बजट-2024-25 में यूपी को केंद्रीय करों में राज्यांश के हिस्से के रूप में 2,18,816 करोड़ मिलने का अनुमान है।
- केंद्रीय बजट में गरीब, महिला, युवा व किसान का विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें अवस्थापना विकास पर अधिक जोर दिया गया है, जिसका सर्वाधिक लाभ यूपी को मिलेगा।